

अध्यक्ष महोदय



असंशोधित

29 MAR. 2001

# बिहार विधान-सभा वादवृत्त

## सरकारी प्रतिवेदन

(भाग १—कार्यवाही—प्रश्नोत्तर)

टर्न-31/29.3.2001/

(70)

श्रीरमण/

श्रीमती रमा देवी : मंत्री : महोदय, 160 लौह निष्काशन संयंत्र का निर्माण किया गया है और 95 संयंत्र का निर्माण शेष रह गया है, जो कोशी अमृत पेय जल योजनांतर्गत करना है, कटिहार जिला में काम जारी है।

अध्यक्ष : कब तक पूरा करवा देंगे शेष का ?

श्रीमती रमा देवी : मंत्री : 2001 में शुरू करेंगे और 6 माह के अन्दर पूरा करवा लेंगे।

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, कार्यपालक अभियंता, कोशी अमृत पेयजल योजना, कटिहार जो वर्तमान कार्यपालक अभियंता के चार-पांच माह पहले तक थे, बदली हुई है।

अध्यक्ष : इसमें प्रश्न नहीं उठता है।

तारांकित प्रश्न सं०-1143

अध्यक्ष : इसमें भी एक पिंदु पर स्का था। यह पिंदु है मंत्री, कृषि विभाग, इसका जवाब अगली तिथि को देंगे कि केन्द्र सरकार को ओर से ~~कितना खर्च हुआ~~ दिया गया विकास के लिये गत वर्ष 60 करोड़ की राशि जो विमुक्त हुई थी, इस क्रम में यह भी जवाब देंगे कि भोजपुर एवं चक्सर में कितना खर्च हुआ ?

श्री. शिव शंकर यादव :राज्यमंत्री:- महोदय, आपने उस दिन कहा था, दूसरी बात, मैं बनाकर पूरा डिटेल् में, व्यापक तौर पर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उस समय जो योजना स्वीकृत हुई थी, उसमें मात्र आफिशियल स्थापना गद पर ही खर्च हुआ था और उसी का बजट था, कोई निकासी नहीं हुई थी, दशम् वित्त आयोग का जो पैसा खर्च हुआ है, जो पैसा आया है....

। व्यवधान।

अध्यक्ष:- आपलोग शांति कायम रखिये । पहले माननीय मंत्री जी को बात को सुन लीजिये।

श्री शिवशंकर यादव :राज्यमंत्री:- महोदय, भारत सरकार ने राज्य सरकार को टाल-दियारा विकास हेतु वर्ष 99-2000 में 52 करोड़ रुपये भेजा था, जिसको प्रशासनिक स्वीकृत भारत सरकार ने 2.3.2000 को भेजा था । भारत सरकार ने दशम् वित्त आयोग से टाल-दियारा के लिए 39 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की है, इसके अन्तर्गत टाल-दियारा सम्बन्धित कृषि हेतु, लघु सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, जल संसाधन विभाग, उर्जा विभाग को निम्न प्रकार से राशि की प्रावधान की गयी है । महोदय, कृषि विभाग को दो करोड़ 26 लाख 97 हजार, लघु सिंचाई विभाग को 2 करोड़ 50 लाख, 19 हजार, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को एक लाख, 60 हजार, जल संसाधन विभाग को 11 करोड़, 16 लाख, 57 हजार एवं उर्जा विभाग को 22 लाख 6 हजार, पानि कुल मिलाकर 39 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गयी है ।

अध्यक्ष:- इसमें जो माननीय मंत्री ने जवाब दिया, विभिन्न विभागों में इसको समीक्षा तो हो नहीं पायेगी, इसलिए इस प्रश्न को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में भेजकर इसकी समीक्षा करायेगी ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह:- महोदय, कहाँ-कहाँ खर्च हुआ, यह तो ये बतावें ?

अध्यक्ष:- अभी तो विभिन्न विभागों में गया है ।

श्री सुशील कुमार मोदी :नेता, विरोधी दल:- अध्यक्ष महोदय, इन्होंने स्वीकार किया कि 39 करोड़ की राशि विमुक्त हो गयी, जिसमें 11 करोड़ 16 लाख, 57 हजार रुपये जल संसाधन विभाग के लिए है । महोदय, राधेन्द्र प्रताप सिंह जी भी इसमें बोलना चाहे रहे हैं, चूंकि जक्सर, भोजपुर इलाका में भयंकर कटाव हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, यह सरकार एक तरफ पैकेज की मांग कर रही है और दूसरी तरफ भारत सरकार से इनको इतना पैसा मिला है, लेकिन ये पैसा खर्च नहीं कर पा रहे हैं । ये बतावें कि इसकी स्थिति क्या है ?

अध्यक्ष:- ये अभी देने की स्थिति में नहीं है ।

(72)

टर्न-32/राजेश/29.3.2001

श्री तुशील कुमार मोदी : नेता, विरोधी दल :- मंत्री जी, आप बताइये कि कंव पैसा आपको मिला ?

श्री शिवशंकर यादव : राज्यमंत्री :- महोदय, 2001 को मिला है ।

अध्यक्ष :- माननीय राज्यमंत्री, आप कृपया बैठ जाइये ।

टर्न-33/29.3.01/सिन्हा ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 1143 का पूरक ।

श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह : **मंत्री** : महोदय, दिवारा ए. विकास बोर्ड का गठन हुआ है और दिवारा क्षेत्र के अनेक समस्याओं पर प्रश्न उठाया गया । यह हमारे क्षेत्र से भी संबंधित है । वक्तर से यह मामला संबंधित है । हम एक ही आग्रह करेंगे कि आप स्वयं इसकी समीक्षा कर लें और जो संबंधित लोग चाहे, मंत्री, पदाधिकारी या विभाजक हों, उनसे विचार-विमर्श कर लें ताकि इसकी सही उपयोगिता हो ।

तारांकित प्रश्न संख्या - 1144

श्रीमती रमा देवी : **मंत्री** : ॥ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वक्तर शहर में वर्तमान में 6 अदद वोरिंग कार्यरत हैं जितने जलापूर्ति दी जा रही है । 4 अदद वोरिंग निष्क्रिय हो गए हैं । इनमें से 2 अदद निष्क्रिय वोरिंग के स्थान पर किला । रागरेखा घाट । एवं नई बाजार में एक-एक अदद वोरिंग एवं पंपे चैम्बर का निर्माण किया जा चुका है । विद्युत संयोजन प्राप्त कर इन्हें चालू करने की कार्रवाई की जा रही है ।

॥ 21 ॥ उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तु स्थिति यह है कि यह योजना वर्ष 1967-68 की है । लेकिन पाईप कहीं फटा नहीं है । इस योजना के उन्नयन हेतु वर्ष 1987-88 में स्वीकृत 71.81 लाख के विरुद्ध मात्र 41.845 लाख रु० ही वक्तर नगरपालिका द्वारा उपलब्ध कराया गया है । उपलब्ध राशि से अधिकांश पाईप लाईन विछाने का कार्य कर लिया गया लेकिन सभी पाईप लाईन को मूल पाईप लाईन से नहीं जोड़ा जा सका है । अतः टी कनेक्शन कई जगहों पर छुटा हुआ है ।

इस योजनान्तर्गत क्लोरिनेटर नहीं लगा है लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ब्लिचिंग पाउडर नियमित रूप से डालकर शुद्ध पेय जलापूर्ति की जाती है ।

॥ 3 ॥ स्वीकृत योजना की शेष राशि 29.965 लाख रूपया नगर विकास विभाग से प्राप्त होने के पश्चात् ही शेष कार्य को किया जाना संभव है । विछाये गये पाईप को टी कनेक्शन आदि के साथ मूल पाईप से जोड़ने के लिए 4.4 लाख की योजना तैयार कर राशि उपलब्ध कराने हेतु जिला